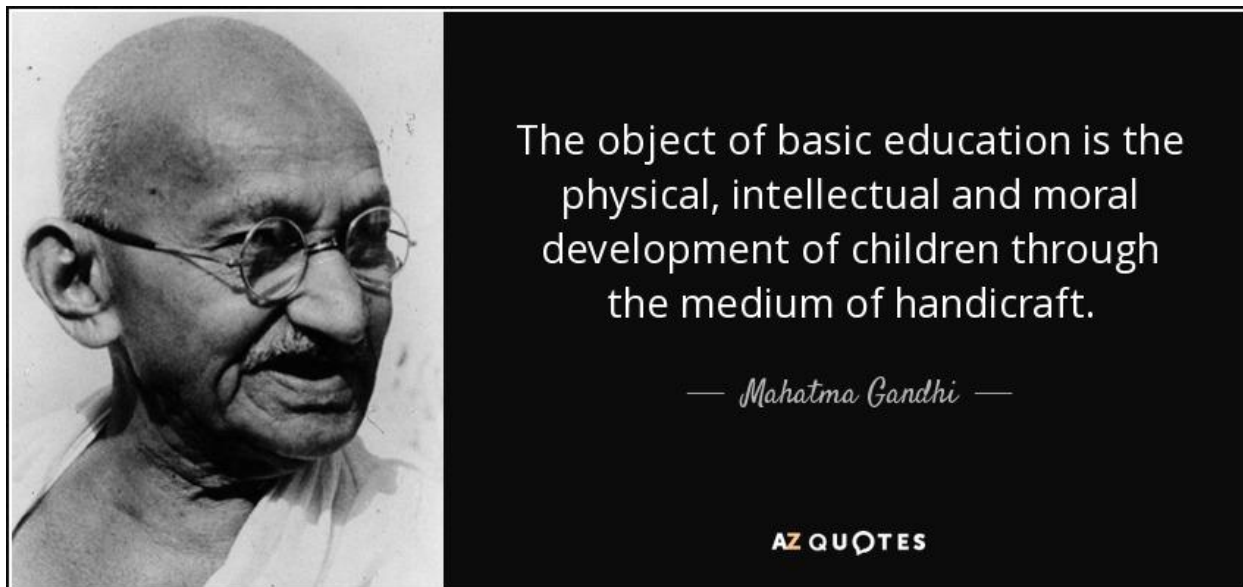


आजादी से पहले उच्च शिक्षा की भूमिका



स्वतंत्रता पूर्व भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास



भारत में शिक्षा का विकास काल :

यह कहा जा सकता है कि भारत में शिक्षा परिदृश्य का विकास प्रत्येक नई अवधि और शासन के आगमन के साथ विभिन्न चरणों में हुआ है। भारत में शिक्षा के स्तरों को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है :

1. वैदिक काल
2. बौद्ध काल
3. मुस्लिम काल
4. ब्रिटिश काल (स्वतंत्रता पूर्व)
5. स्वतंत्रता के बाद का काल

• वैदिक काल :

इस समय के दौरान शिक्षा निशुल्क थी जहाँ गुरु अपने छात्रों के लिए भोजन-आवास की व्यवस्था करते थे।

वे मुख्य रूप से अपने धर्म और मोक्ष के उपदेश पर आधारित थे। वे या तो मौखिक रूप से या मानस के माध्यम से, प्रतिबिंब विधि सिखाते थे।

- **बौद्ध काल** : भारत में जन्में गौतम बुद्ध बौद्ध शिक्षा प्रणाली के संस्थापक थे। वे अपने चार महान सत्य पर विश्वास करते थे। पबजा समारोह के बाद छात्र को बौद्ध मठ में ले जाया जाता था।

12 साल की शिक्षा के बाद वे उपसम्पदा से गुजरते हैं और एक भिक्षु बन जाते हैं। उन्होंने मौखिक शिक्षण का पालन किया जहां वे प्रश्न उत्तर सत्र, तर्क और सम्मेलन सत्र आयोजित करते थे।

- **इस्लामिक काल :**

यह शिक्षा प्रणाली तब शुरू हुई जब मुस्लिम शासकों ने मध्यकाल में शासन करना शुरू किया। इस प्रणाली को मकतब-मदरशा प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था।

यह प्रणाली मुस्लिम संस्कृति के ज्ञान को विकसित करने, इस्लामिक धर्म के प्रसार और चरित्र तथा नैतिकता के विकास पर जोर देती है।

उनके शिक्षकों को उस्ताद और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था।

- **ब्रिटिश काल :**

मुस्लिम शासन के खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन किया। 150 वर्षों तक उनके शासन के दौरान भारत ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य में अपना विकास देखा।

भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली में जो सफलता देखी, वह बड़े पैमाने पर थी। मुस्लिम शासन के पतन के बाद, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए। अंग्रेजों ने दो सौ से अधिक वर्षों तक भारत पर शासन किया, 1858-1947 तक विस्तारित शासन की स्थापना 1858 में की गई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को महारानी विक्टोरिया (जिन्हें 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया था) के नाम पर क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था।

- अंग्रेजों के आगमन के साथ, उनकी नीतियां सीखने के पारंपरिक स्कूलों की समृद्ध विरासतों के साथ आई थीं, जो लोगों में समग्र विकास और मूल्य वृद्धि पर केंद्रित थीं। उनकी शिक्षा नीतियों को अधीनस्थों का एक वर्ग बनाने की दिशा में निर्देशित किया गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का एक भारतीय संस्करण बनाने के लिए कई अधिनियमों का गठन किया जो किसी भी तरह से भारतीयों की बेहतरी के लिए नहीं थे।
- शुरुआत में अंग्रेज किसी भी प्रयास के माध्यम से भारतीय समाज में योगदान देने का कोई इरादा नहीं रखने वाले व्यापारियों के रूप में आए थे, बाद में उन्हें अपनी प्रजा के आध्यात्मिक और शास्त्रीय शैक्षिक उत्थान के अलावा कुछ करने की आवश्यकता महसूस हुई।

- वे हिंदू और अंग्रेज दोनों समुदायों की सहानुभूति और समर्थन जीतना चाहते थे; इसलिए अक्टूबर 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मदरसा की नींव रखी गई तथा हिंदुओं के लिए, जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा और इसके विकास के लिए कई कार्य किए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :-

- 1) **1813 का चार्टर अधिनियम** : ब्रिटिश संसद में हर 20 साल में चार्टर अधिनियम का नवीनीकरण किया जाता था। जब यह 1813 में नवीकरण के लिए आया, तो इसने कंपनी को आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने और युवा भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए सालाना एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया। इस उद्देश्य के लिए एक लाख रुपये की मामूली राशि आवंटित की गई थी।

एक **आंग्लिक-प्राच्य विवाद** था, आंग्लिक ने तर्क दिया शिक्षा केवल आधुनिक अध्ययन के लिए की जाना चाहिए। दूसरी ओर प्राच्य की राय थी कि पश्चिमी विज्ञानों को नौकरियों के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन पारंपरिक भारतीय शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया जाना चाहिए।

- 2) **लॉर्ड मैकाले का कार्यवृत्त (1835)** : प्राच्य और आंग्लिक सवाल पर बहस को 20 साल के बाद अर्थात् 1833 में अगले चार्टर अधिनियम तक भी हल नहीं किया जा सका। तब गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी सदस्य के रूप में 10 जून 1835 को लॉर्ड मैकाले भारत आया। उन्हें यह बताने का काम दिया गया कि शिक्षा पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये कैसे खर्च किए जाएं और कैसे विवाद को भी हल किया जाए।

- उसने अपनी रिपोर्ट आंग्लिकों के पक्ष में दी। उसने कहा कि "भारतीय अध्ययन यूरोपीय अध्ययन से कमतर था। अंग्रेजी को स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम बनाया गया और बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूलों के बजाय उनमें से कुछ को खोला गया।
- यह योजना उच्च और मध्यम वर्ग के भारतीयों के एक छोटे से वर्ग को शिक्षित करने के लिए थी, जो "रक्त और रंग में भारतीय लेकिन रुचि, राय और बुद्धि से अंग्रेज" का एक वर्ग बनाने के लिए थी।
- शिक्षित भारतीयों का यह वर्ग अपने विचारों के माध्यम से जनता को शिक्षित करेगा और इसे "अधोमुखी निःस्यंदन सिद्धांत" कहा जाएगा।

- 3) **थॉम्पसन के प्रयास** : उत्तर-पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉम्पसन ने ग्राम शिक्षा की एक व्यापक योजना विकसित की। इस योजना क्षेत्रमिति और कृषि जैसे उपयोगी विषय पढ़ाए गए थे।

4) वुड का घोषणा पत्र (1854)

20 वर्षों के अंतराल के बाद, ब्रिटिश संसद को चार्टर एक्ट को फिर से नवीनीकृत करना था। 1854 में, चार्ल्स वुड ने भारत की शिक्षा प्रणाली पर एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे "भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैगना कार्टा" माना जाता है। इस घोषणा पत्र की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित थी :-

- महिला और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर।
- धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया।
- उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में और स्कूल स्तर पर मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी की अनुशंसा
- इसने अधोमुखी निरस्यंदन सिद्धांत का खण्डन किया और सरकार से जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने को कहा।
- कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए।

5) हंटर शिक्षा आयोग (1882-83):

पिछली योजनाओं ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की उपेक्षा की। प्रांतों को शिक्षा के हस्तांतरण के कारण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को 1870 के बाद नुकसान उठाना पड़ा। डब्ल्यू. डब्ल्यू. हंटर के अधीन एक आयोग को 1854 के बाद से देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए निर्धारित किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित थीं :-

- प्राथमिक शिक्षा को नव स्थापित जिलों और नगरपालिका बोर्डों में स्थानांतरण।
- यह सिफारिश की गई कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में दो विभाग (साहित्यिक और व्यावसायिक) होने चाहिए।

6) भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 :

20^{वीं} सदी के दौरान, शिक्षा की गुणवत्ता निजी प्रबंधन के तहत बिगड़ने लगी। राष्ट्रवादियों ने सरकार पर निरक्षरता उन्मूलन के लिए कुछ भी नहीं करने का आरोप लगाया। परिणामस्वरूप, 1902 में विश्वविद्यालयों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के लिए रेले आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 के माध्यम से प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पर सिफारिशें दीं। इसे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था।

7) **सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-19) :-**

इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए किया गया था और उनकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू थीं।

- उनके अवलोकन इस प्रकार थे:

- I. 12 साल का स्कूल पाठ्यक्रम
- II. मध्यवर्ती चरण के बाद 3 साल की उपाधि
- III. विश्वविद्यालयों का केंद्रीकृत कामकाज
- IV. अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और महिला शिक्षा के लिए विस्तारित सुविधाओं पर जोर दिया गया।

8) **हार्टोग कमेटी (1929) :**

बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों के कारण शिक्षा का स्तर बिगड़ गया था।

- हार्टोग कमेटी ने सुझाव दिया कि बिना किसी जल्दबाजी के विस्तार के साथ प्राथमिक शिक्षा पर उचित जोर दिया जाना चाहिए।
- योग्य छात्रों को हाई स्कूल में प्रवेश करना चाहिए, जबकि औसत छात्रों को 8^{वीं} कक्षा के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भेज दिया जाना चाहिए।

9) **वर्धा शिक्षा योजना :**

- यह एक योजना थी जिसे गांधीजी ने स्वयं लिखा था, जिन्होंने 22 अक्टूबर 1937 को शिक्षा के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था।
- अन्य समाज सुधारकों और शिक्षाविदों के साथ 7 साल तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए सौदे किए गए जो उत्पादक थे और मातृभाषा में पढ़ाए जाते थे।

10) **डॉ. ज़ाकिर हुसैन समिति, 1937 :**

- भारतीय शिक्षा प्रणाली को अंतिम रूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन के बाद दिया गया था, जहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जाकिर हुसैन ने एक रिपोर्ट पेश की थी।
- यह दर्शाता है और निष्कर्ष निकालता है कि हालांकि बुनियादी गांधीवादी शिक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था लेकिन यह पूरी तरह विफल थी। एकमात्र प्रासंगिकता यह थी कि सामग्री को मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा था और प्राच्य सामग्री पढ़ाई जा रही थी।

11) **सार्जेंट शिक्षा योजना :**

सार्जेंट शिक्षा योजना 1944 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई थी। इसकी सिफारिशें थीं :

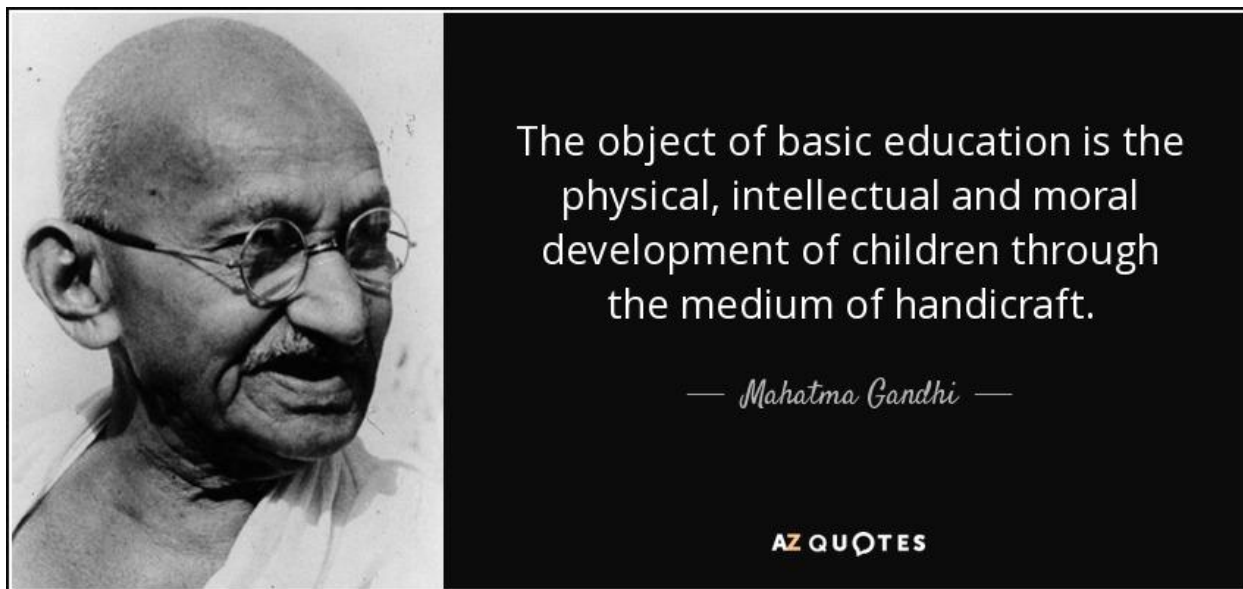
- 3-6 वर्ष आयु समूह के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, 6-11 वर्ष आयु वर्ग के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा।
- पर्याप्त तकनीकी, वाणिज्यिक और कला शिक्षा।
- माध्यमिक पाठ्यक्रम की समाप्ति।

इसलिए, ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा हमेशा ब्रिटिश लोगों की जरूरतों और मांगों के अनुरूप विकसित की गई थी, न कि भारतीय लोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए।

वे भारतीय लोगों को उनके लिए काम करने में सक्षम बनाना चाहते थे न कि उनके देश के विकास के लिए।



Evolution Of Higher Learning And Research In Pre- Independence India



Periods Of Development Of The Education In India:

The education scenario in India could be said to be developed in various stages with the advent of each new period and rule. The stages of education in India could be divided into the following stages:

1. The Vedic Era
2. The Buddhist Era
3. The Muslim Era
4. The British Era (Pre Independence Era)
5. Post Independence Era

• The Vedic Era:

During this time the education was free where the Gurus would arrange boarding for their students.

They were mainly based on preaching their religion and salvation. They would teach either orally or through Manas, the reflection method.

- **The Buddhist Era:**

Gautama Buddha born in India was the founder of the Buddhist education system. They believed in their four noble truths. The student would be taken into the Buddhist monastery after performing the Pabbaja Ceremony.

After 12 years of education they undergo Upasampada and become a monk. They followed oral teaching where they would conduct question answer sessions, logic and conference sessions as well.

- **The Islamic Era:**

This education system commenced when the Muslim rulers started ruling in the Medieval Period. This system was also known as the Maktab-Madarsha system.

This system emphasizes on developing knowledge of the Muslim culture, spreading the Islamic religion and on developing character and morality

Their teachers were called Ustads and the students, Shagird.

- **The British Era:**

The British made their way into India after the Muslim rule was pulled down. During their rule for over 150 years India saw a development in its western science and literature through the English Language.

The breakthrough that India saw in its education system was massive. After the downfall of the Muslim rule, The Britishers came to India as a trading company under the name of East India company. The British ruled India for more than two-hundred years, the rule spanning from 1858- 1947. The system of governance was instituted in 1858 when the rule of the East India Company was transferred to the Crown in the name of Queen Victoria (who in 1876 was proclaimed Empress of India).

- With the advent of the British, their policies were at odds with the rich legacies of traditional schools of learning which focussed on the overall development and

value inculcation in the people. Their education policies were directed toward creating a class of subordinates. To achieve this goal, they instituted a number of acts to create an Indian version of English education which were not for the betterment of Indians in any way.

- In the beginning the British came as traders with no intention of contributing to the Indian society through any efforts, later they felt the need to do something apart from the spiritual and classical educational upliftment of their subjects.
- They wanted to win the sympathy and support of both Hindu and English communities; hence the foundations of Madrasa were laid by Warren Hastings in Oct 1780. For Hindus, Jonathan Duncan founded the Banaras Sanskrit college in 1791.

There were various acts that were established for the education and its development in India during the British rule. Few of the important ones are as follows: -

- 1) **The Charter Act of 1813:** The charter act was renewed every 20 years in the British parliament. When it came for renewal in the year 1813, it directed the company to sanction one lakh rupees annually for promoting knowledge of modern sciences and encouraging the young Indians. A modest amount of one lakh rupees were allotted for the purpose.

There was an **Anglicist- Orientalist Controversy**, The Anglicist argued the education should be only for the modern studies. The Orientalist on the other hand were of the opinion that western sciences were taught for the jobs but emphasis should be laid on the expansion of traditional Indian learning.

- 2) **Lord Macaulay's Minutes (1835):** The debate over the orientalist and Anglicist question could not be solved even till the next charter act after 20 years i.e. 1833. Then Lord Macaulay came to India on 10th June 1835, as law member of the Governor General's council. He was given the task to tell how to spend 10 lakh rupees per annum on education and also solve the controversy.

- He gave his report in the favour of the Angelist. He held the view “Indian Learning was inferior to the European learning. English was made as the medium of education in schools and colleges and opened few of them instead of large number of elementary schools.
- The plan was to educate a small section of the upper and middle class Indians creating a class “Indian in blood and colour but English in tastes, opinions and intellect”.
- This section of educated Indian would educate the masses through their ideas and it will be called “**Downward filtration theory**”.

3) **Efforts of Thompson:** James Thompson, lieutenant Governor of the North - western Province developed a comprehensive scheme of village education. In this scheme useful subjects like mensuration and agriculture were taught.

4) **Wood's Despatch (1854):** After the lapse of 20 years, the British parliament has to renew the charter act again. IN 1854, Charles Wood prepared a despatch on the education system of India, which is considered as “Magna Carta of English Education in India.” These were the few recommendations of the despatch: -

- Stress on female and vocational education and teachers' training.
- Laid emphasis on secular education
- Recommended English as the medium of instruction for higher studies and vernaculars at school level
- It repudiated the downward filtration theory, and asked the government to assume responsibility of the education of masses.
- Universities of Calcutta, Bombay and Madras were set up in 1857 and later department of education were set up in all provinces.

5) **Hunter Education Commission (1882-83):**

The previous schemes neglected the primary and secondary education. The Primary and secondary education further suffered after 1870, due to the transfer

of education to the provinces. A commission under W. W Hunter was set to review the progress of education in the country since the despatch of 1854.

Few of the important recommendations were :-

- Transfer of primary education to newly set up district and municipal boards.
- Recommended that secondary education department should have two divisions (literary and vocational)

6) **Indian University Act, 1904:-** During 20th century, the quality of education started deteriorating under private management. Nationalist accused the government of not doing anything to eradicate illiteracy. Consequently, in 1902 Rayleigh Commission was set up to improve the working conditions of the Universities. The commission gave recommendations on the primary or secondary education through the Indian Universities Act, 1904. It was passed during the tenure of Lord Curzon.

7) **Sadler University Commission (1917-19):** - It was formed to report the problems Calcutta University and their recommendations were applicable to other universities also.

- Their observations were as follows:

I. 12-year school course

II. 3-years degree post the intermediate stage

III. Centralised functioning of the universities

IV. extended facilities for applied scientific and technological education, teacher's training and female education were emphasised.

8) **Hartog Committee (1929):**

Due to large number of schools and colleges had led to the deterioration of education standards.

- Hartog Committee suggested there should be proper emphasis on the primary education with no hasty expansion.

- Deserving students should get into high school while average students should be diverted to vocational courses after 8th standard.

9) WARDHA SCHEME OF EDUCATION:

- This was a scheme that was written by Gandhiji himself who took part in an All Indian National Conference for education on 22 October 1937.
- Deals were made along with other social reformers and educationalists to bring free education for 7 years that is productive and taught in the mother tongue.

10) DR. ZAKIR HUSSAIN COMMITTEE, 1937:

- The final shape to the Indian Education System was given after the All India National Educational Conference where Dr. Zakir Hussain the Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia University had presented a report.
- It shows and concludes that though the Basic Gandhian Education system was accepted it was a total failure. The only relevance it had was the content being taught in mother tongue and oriental content being taught.

11) Sergeant plan of Education: The Sergeant plan of education was given by the Central Advisory Board of Education in 1944. Its recommendations were:

- Pre -primary education for 3-6 years age group, free universal and compulsory elementary education for 6-11 years age groups.
- Adequate technical, commercial and arts education
- Abolition of intermediate course.

Therefore, the education during the British era was always developed to suit the needs and demands of the British people and not to promote the development of the Indian people.

They wanted to produce Indian people able to work for them and not for the development of their country.